चल रही है। अब स्टेट गवर्नमेंट कार्यवाही कर रही या नहीं कर रही है लेकिन जितना भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, वह इफेक्टिव नहीं है, यह हम मानते हैं। इसलिए इफेक्टिव तौर पर पूरा पिलफ़ेज 100 परसेंट पिलफ़ेज रोकने के लिए क्या कार्यवाही करनी चाहिए, यह दिल्ली में बैठ कर तो आप और हम नहीं कर सकते हैं। हमारे आफिसर वहां पर जा रहे हैं और वहां जा कर के वहां के आफिसरों से बात करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेन्टेटिव्ज से भी बात करेंगे। जहां जहां पिल्फ़ेज हुआ है, कैसे हुआ और उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए यह सब देखेंगे। पूरे पाईप लाइन का भी इन्स्पेक्शन करेंगे। उसके बाद वे आई० ओ० सी० के चेअरमैन को रिपोर्ट देंगे।

अब तक आई० ओ० सी० का चेअरमेन वहां क्यों नहीं गया है? इसका मुझे मालुम नहीं है कि चेअरमेन कितने मर्तबा वहां गये हैं। वैसे तो जहां जहां हमारी रिफाइनरीज हैं, जहां डिपोज हैं, पूरे तौर पर उनको रखने का उनका काम है। हमेशा वे जाते रहते हैं। मुमकिन है कि वे मद्रास भी गये हों। इस सिलसिले में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं इसलिए मैं उन्हें नहीं दे सकता हूं। लेकिन इंकवायरी कर के बहुत से हमारे लोकल आफिसर्स गवर्नमेंट को रिपोर्ट देने के लिए वहां हैं। बहुत से लोकल आफिसर्स ने आई० ओ० सी० के चेअरमेन को रिपोर्ट दी है और आई०ओ०सी० के चेअरमेन ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी है।

यह कहना गलत है कि अखबार में आने के बाद हमारी आंखें खुली या कालिंग अटेंशन आने के बाद हमने आंखें खोलीं। यह 1976 से चल रहा है और हमारे आफिसर्स ने जो कोरेस्पोन्डेंस की जो रिपोर्ट पुलिस को, आई०जी० को और पुलिस कमिश्नर को की वे ये हैं— 7-4-78, 1-6-78, 13-12-78, 19-7-78, 19-7-79, 28-7-79, 19-11-79, 4-12-79, 3-6-1980 महीने दो महीने से हमारे आफिसर्स रिपोर्ट भेजते रहे हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि इतना तमाम हमारे आफिसर्स के करने के बाद भी पिल्फ़ेज रुका नहीं है, यह बात है। इसलिए हम कहते हैं कि रूटीन तौर पर इसे हम नहीं देख सकते हैं। इसके लिए कोई सीरियस कार्यवाही होनी चाहिए। इसलिए हमारे आफिसर्स की रिपोर्ट आने के बाद हम आगे कार्यवाही करेंगे।

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: Whether there are detective signals or not?

SHRI VEERENDRA PATIL: It is a small line. It is only 9.3 kilometres there are no detectives.

12.54 hrs

DELHI MUNICIPAL LAWS (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Punjab Municipal Act, 1911, as in force in New Delhi, and the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Punjab Municipal Act, 1911, as in force in New Delhi, and the Delhi Municipal Corporation Act, 1957."

The Supreme Court in the recent

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): सभापति महोदय, इसमें मेरा विरोध है। सभापति जी मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब विधेयक पेश किया जाता है तो उसका विरोध नहीं होता है। लकिन इस विधेयक में एक विशेष परिस्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है 30 दिसम्बर, 1979 को और उस फैसले के अनुसार यह आदेश दिया गया कि दिल्ली में मकानों या अन्य जायदादों के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका निर्धारण करते समय दिल्ली के रेन्ट कंट्रोल एक्ट को ध्यान में रखना चाहिये। सरकार ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कार्यान्वित करने के लिये कार्रवाई की जायेगी। एक सवाल पूछा गया था 18 जून, 1980 को और श्री योगेन्द्र मकवाणा ने उत्तर दिया था। सवाल था:

Whether Supreme Court has recently given any verdict about not increasing the rateable value?

मंत्री महोदय का जवाब था:

judgement has laid down that the reasonable rental value of the property can only be fixed with reference to the provisions of Delhi Rent Control Act. This decision of the court is being implemented by the Corporation.

अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कार्यान्वित करन का तरीका कौन सा अपनाया जा रहा है? सरकार जो कानून ला रही है उसका नतीजा यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रख दिया जाएगा और सरकार ने कानून को जो रूप दिया है उसको आप पढ़ें। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस कानून को इस रूप में पेश न करें। इसे वापिस ले लें। कोई जल्दी नहीं है। यह कानून गम्भीर विचार विनियम के बाद लाया जाना चाहिये। हम किस तरह का कानून बनाने जा रहे हैं, इसको आप देखें। इस संशोधन विधेयक की धारा 3 में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है:

"Explanation.—For the purposes of this section, the expression 'the annual rent at which such land or building might reasonably be expected to let" shall, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, mean and be deemed always to have meant the actual rent received or receivable for such land or building or the standard rent determined for such land or building under, or, as the case may be, in accordance with the principles laid down in, the law relating to control of rents...."

What is 'receivable'? यह कौन तय करेगा कि रिसीवैबल रैन्ट कौन सा है? क्या यह अफसरों को मनमानी अधिकार देने का तरीका नहीं है? क्या यह भेदभावपूर्ण नहीं होगा? क्या इस प्रावधान का लाभ उठा कर नागरिक परेशान नहीं किये जायेंगे?

जिस सवाल का मैंने हवाला दिया था उसी में एक प्रश्न पूछा गया था:

Whether there could be different rateable values for the houses having equal covered area?

मंत्री महोदय का उत्तर था:

According to the Municipal Corporation of Delhi there can be different rateable value for the houses having equal covered area and the rateable value can be increased as a result of construction of only one additional room depending upon the merits of each case.

सवाल पूछा गया था कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि अगर कोई एक कमरा बनाये तो कहीं तो उसे 380 रुपया देना पड़े और कहीं 1080 रुपया और मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसी स्थिति हो सकती है । जो मकान किराये पर दिया जाता है उसके बारे में अगर अधिक टैक्स लिया जाये तो समझ में आ सकता है लेकिन जिस आदमी ने अपने रहने के लिये मकान बनाया है क्या उस पर भी जायदाद के कर की दर वही रखी जानी चाहिये ।

SHRI MOOL CHAND DAGA (Pali): I am on a point of order.

Can the Member, at this stage, raise these points? This is just introduction stage. His speech has to be on legislative competence.

MR. CHAIRMAN: My reading is certain he has a right to go into the principle even at this stage when leave is sought.

श्री अटल बिहारी वाजपयी : अगर मैं चाहता तो इस कानून को बनाने के बारे में सदन की सवैधानिक क्षमता को चुनौती दे सकता था लेकिन मैं ऐसा नही कर रहा हूं । मुझे कहने का पूरा अधिकार है कि इस कानून को जिस स्वरूप में पेश किया जा रहा है वह नितान्त अस्पष्ट है ।

13.00 hrs.

वह भेदभाव को बढ़ावा देने वाला होगा । उसे पारित करने का अर्थ न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखना होगा, बल्कि अधिकारियों को इस तरह के अधिकार देना होगा, जिनका उपयोग नागरिकों के विरुद्ध हो सकता है खासकर उन नागरिकों के विरुद्ध, जिन्होंने अपनी कमाई से अपने रहने के लिए मकान बनाये है । मेरा निवेदन है कि यह मामला गहरा पेंचीदा और उलझा हुआ है । इस सम्बन्ध में दिल्ली के नागरिकों की राय लेनी चाहिए । इस बारे में दिल्ली के पार्लियामेंट के मेम्बरों की सलाह भी नहीं ली गई है । मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय इस बिल को जल्दी पास करने की कोशिश न करें ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: So far as the advice from the Members is concerned, when the Bill is discussed it will automatically come from the Members and we will consider it. He quoted my replies in Parliament. I stand by it even today. So long as the decision of the court stands, it is to be implemented, but in order to avoid it or in order to nullify it, I am introducing this Bill. When the Bill comes into effect, then the position will change. At present the position is such that as every Member of this House knows, the income of the New Delhi Municipal Committee and the Delhi Municipal Corporation is from the house tax. Now, if the tax is removed, then what will be the position of these two bodies? Every institution requires some income and every such income can be received only through imposition of some tax in one way or the other. Here, this is recovered through tax. If this position continues as it is, then the New Delhi Municipal Committee will lose nearly Rs. 2 crores annually whereas the Delhi Municipal Corporation will lose Rs. 5 crores. Not only this, but the refund which will have to be paid by the New Delhi Municipal Committee will be Rs. 15 crores. Now, in such a position, to overcome all these difficulties, the Bill is being introduced and in the Statement of Objects and Reasons (*Interruptions*) I have fully explained why this Bill is introduced and in view of all this, I would like the hon. Member not to raise any objection at this stage. When the Bill comes before the House for discussion, he is at liberty to discuss. Whatever points he wants to raise at that time he may raise and we will consider them.

MR. CHAIRMAN: You approach this issue with an open mind.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Open mind does not mean vacant mind. The mind should be open, but it should not be vacant.

MR. CHAIRMAN: The presumption is that the mind is not vacant.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: There is no State Assembly for this. Parliament has to enact all laws. I would like to know whether the Minister will be prepared to refer the whole Bill to the Select Committee.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: That will be done at an appropriate stage. This is not the stage to suggest whether it would be referred to the Select Committee. Let it come, then we will consider it in the House. It is for the House and not for me to decide.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Punjab Municipal Act, 1911, as in force in New Delhi, and the Delhi Municipal Corporation Act, 1957."

The motion was adopted.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I introduce the Bill.

(*Interruptions*).

13.05 hrs.

HIGH COURT AND SUPREME COURT JUDGES (CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI P. SHIV SHANKAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954, and the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Act, 1958.

SHRI JYTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I am very constrained to say....

MR. CHAIRMAN: I think you will throw some jyoti, light.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I do not know whether I will succeed or not, it is up to you to judge. I do not know why my parents have chosen that name for me, because I think it is a very wrong thing to do.

MR. CHAIRMAN: The Chair only wanted to tell you that you should not shed so much light that people may become blind!

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am most constrained to say that *(*Interruptions*).

SHRI P. SHIV SHANKAR: On a point of order. Nothing should be on record with reference to these matters.

MR. CHAIRMAN: Against a sitting Judge, nothing can be said.

SHRI P. SHIV SHANKAR: Whatever he has said should be expunged from the records.

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Kindly read article 121. It is made clear there that no discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties....

SHRI P. SHIV SHANKAR: Extraneous matters should not be recorded.

SHRI JYOTIRMOY BOSU:* *

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI VASANT SATHE): Such unparliamentary remarks should not be allowed.

**Expunged as ordered by the Chair.